



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

स्वदेशी अपनाएं
आत्मनिर्भर राजस्थान बनाएं

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 75 वें जन्मदिन
से प्रेरित जनसेवा अभियान

सेवा शिविरों से मिली आम जनता को बड़ी राहत

1.95 लाख +
पट्टे वितरण

1.17 लाख +
फार्मर रजिस्ट्री में नए पंजीयन

1.53 लाख +
भू-राजस्व शुद्धिकरण
प्रकरणों का निस्तारण

1.24 लाख +
नामान्तरण प्रकरणों का निस्तारण

2.60 लाख +
मंगला पशु बीमा योजना पॉलिसी

1.72 लाख +
मूल निवास प्रमाण पत्र

2.04 लाख +
जाति प्रमाण पत्र
वितरण

1.25 लाख +
जन्म, मृत्यु एवं
विवाह पंजीयन

1.98 लाख +
सामाजिक सुरक्षा
पेंशनर्स सत्यापन

95.8 हजार +
खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर
आवेदनों की स्वीकृति

25 हजार +
स्वनिधि योजनांतर्गत
ऋण आवेदन

1.48 लाख +
जनधन योजना में
बैंक खाते खोले

1.13 लाख +
जन आधार योजना में
अद्यतन / संशोधन

75.6 हजार +
वय वंदन कार्ड जारी

17.06 लाख +
किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं
की एनीमिया की जांच

10.77 लाख +
नागरिकों की
टी.बी. रोग स्क्रीनिंग

24.36 लाख +
लोगों का स्वास्थ्य
शिविर में उपचार

1.42 लाख +
नई स्ट्रीट लाइट / सुधार

युवा नेताओं को जिलाध्यक्ष के रूप में पनपाने की योजना फेल हुई राजस्थान में

पुराने नेता, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा, सी.पी. जोशी व जूली संगठित हुए अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए

—रेणु मित्तल—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया, जो राहुल गांधी का विशेष रुप से प्रिय प्रोजेक्ट था, अब मज़ाक बन चुकी है। वरिष्ठ नेता अपने-अपने क्षेत्रों में अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनवाने की कोशिश में एकजुट हो गए हैं।

सभी पर्यवेक्षकों ने कल अपनी रिपोर्टें जमा कर दीं और अब अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व को लेना है। लेकिन इसी बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नामों का एक पैनल सौंप दिया है, जो पूरी तरह अनावश्यक और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रंधावा के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता एकजुट होकर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

सी.पी. जोशी अपने क्षेत्र में अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, और जब भी किसी के नाम का प्रस्ताव रखा जाता है, सभी तुरंत हां में हां मिला देते हैं।

विधाक दल के नेता जूली को भी

- उनकी “राय” पर प्रभारी रंधावा अपनी मोहर लगा रहे हैं।

- कांग्रेस के नेताओं ने अध्यक्ष खड़गे व राहुल गांधी को इस मुतल्लिक ज्ञापन भी दिये हैं, किन्तु उनकी शिकायतें अनुसूनी सी रह गई हैं।

- डोटासरा के उम्मीदवारों पुष्पेन्द्र भारद्वाज और सुनील शर्मा के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखे हैं, क्योंकि पुष्पेन्द्र भारद्वाज के खिलाफ कई मामले हैं और सुनील शर्मा, जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, का भारी विरोध होने के कारण खुद सोनिया गांधी ने टिकट काट दिया था।

बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पुष्पेन्द्र भारद्वाज और सुनील शर्मा के खिलाफ पत्र लिखे हैं, जिन्हें डोटासरा ने उम्मीदवार बनाया है। भारद्वाज पर मुकदमे चल रहे हैं और कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं, सुनील शर्मा की जयपुर

विधानसभा उम्मीदवारी पहले ही सोनिया गांधी ने रद्द कर दी थी, क्योंकि शशि थरूर ने उनके खिलाफ ट्वीट किया था। शर्मा ने दोनों गांधी नेताओं को “तानाशाह” कहा था।

राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, वह राहुल गांधी की उस मूल पहल की भावना के खिलाफ है, जिसका उद्देश्य जिलाध्यक्षों को सशक्त बनाना और योग्य व नई नेतृत्व क्षमता वाले लोगों

को सामने लाना था, ताकि पार्टी को लाभ हो सके। लेकिन हो यह रहा है कि वही पुराने नेता अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए पहले से बदनाम और हार चुके चेहरों को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे नई नेतृत्व पंक्ति उभर नहीं पा रही।

और अगर एआईसीसी के प्रभारी महासचिव, इस मामले में रंधावा भी इसमें शामिल हैं, तो कार्यकर्ताओं के पास शिकायत करने या न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं बचता।

राजस्थान में यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जब से अशोक गहलोत ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके महासचिवों की प्रभावित कर पार्टी पर मजबूत पकड़ बना ली थी। के.सी. वेणुगोपाल भी इस पूरी चाल में शामिल माने जा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रंधावा के गहलोत, जोशी, डोटासरा और अन्य कई नेताओं से मजबूत संबंध हैं। राहुल गांधी की अब अपनी आंखें खोलनी होंगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन राज्यों में चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

दस से पन्द्रह राज्यों में अगले सप्ताह से एस.आई.आर. शुरू होगी

— जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। भारत का निर्वाचन आयोग अगले हफ्ते से देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) का पहला चरण शुरू कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान “10 से 15”

- इनमें असम, तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं।

राज्यों में एक साथ शुरू होगा, जिसमें वो राज्य भी शामिल हैं, जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं।

असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे और ये उन राज्यों में शामिल हैं, जहाँ मतदाता सूची संशोधन का काम (शेष पृष्ठ 4 पर)

मुख्यमंत्री ने अकलेरा व श्रीगंगानगर मंडी के विकास कार्य को मंजूरी दी

जयपुर, 25 अक्टूबर। कृषि क्षेत्र में सुविधाओं एवं सेवाओं का विस्तार कर किसान कल्याण के लक्ष्य को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की अकलेरा एवं श्रीगंगानगर मंडी

- दोनों मंडियों में विकास के लिए 2.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

में विकास कार्य के लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। झालावाड़ जिले की कृषि उपज मंडी अकलेरा में ई-नाम हॉल के कार्यालय भवन सहित नवीन निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, कृषि उपज मंडी श्रीगंगानगर के फल-सब्जी व वन उपज मंडी यार्ड में विद्युत कार्यों के लिए भी लगभग 50 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 के तहत टोंक जिले में कृषि उपज मंडी टोडारयासिंह के प्रथम बोर्ड के गठन का अनुमोदन भी किया गया है। जिससे इस मंडी का प्रशासनिक संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

‘मई 2025 में एलआईसी ने अडानी समूह में 33,000 करोड़ रुपए लगाए थे’

वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि यह पैसा 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की बचत का था

- वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर में बताया गया है कि उसके पास जो आंतरिक दस्तावेज हैं उनसे पता चला है कि सरकार के अधिकारियों ने एलआईसी द्वारा अडानी की कंपनी के 33,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तैयार किया था।

- अखबार कहता है कि इस निवेश का लक्ष्य है, अन्य निवेशकों को अडानी ग्रुप में निवेश के लिए प्रेरित करना।

पारित किया। इसके उद्देश्य थे— “अडानी ग्रुप में विश्वास का संकेत देना” और “अन्य निवेशकों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना”।

इस पूरे मोदी-अडानी मेगा घोटाले की जांच केवल एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जा सकती है, जिसकी माँग कांग्रेस पार्टी लगभग तीन वर्षों से

कर रही है—जब से उसने अपनी 100 सवालों की श्रृंखला “हम अडानी के हैं कौन?” (एचएएचके) प्रकाशित की थी।

पहला कदम यह होना चाहिए कि कम से कम संसद की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी (पीएसी) पूरी तरह से यह जांचे कि एलआईसी को वास्तव में अडानी ग्रुप में निवेश करने के लिए

कैसे मजबूर किया गया। यह पीएसी के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से आता है।”

कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि सवाल यह उठता है कि किस दबाव में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि उनका काम एक निजी कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों से उबारना था, जो गंभीर अपराधिक आरोपों के कारण संकट में थी। उन्होंने इसे “मोबाइल फोन बैंकिंग” का मामला बताया।

जयराम रमेश ने कहा, जब सार्वजनिक संसद को प्रश्न कंपनियों को दिया गया, तब यह स्पष्ट हुआ कि एलआईसी ने 21 सितंबर 2024 को केवल चार घंटे की ट्रेडिंग में 7850 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया, इसके (शेष पृष्ठ 4 पर)

राजस्थान में 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले

जयपुर, 25 अक्टूबर। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात एक आदेश जारी कर 67 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें से 24 को

- इनमें से 24 को एसडीएम लगाया गया है।

एसडीएम लगाया गया है। तबादला सूची में उन आरएएस अफसरों का नाम भी है, जो दो दिन पहले ही पदेनत्र हुए थे। आदेश के अनुसार गजेन्द्र सिंह राठौड़ को सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, भागचंद बघाल को जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त, दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव के पद पर लगाया गया है। गुंजन सोनी को संस्कृत विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, संजय कुमार माथुर को एडीएम तृतीय जयपुर, नरेन्द्र कुमार वर्मा को अतिरिक्त कलक्टर जयपुर पूर्व के पद पर लगाया गया है।

नियुक्ति के बाद चयन निरस्त करने पर रोक

जयपुर, 25 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर भर्ती-2023 में नियुक्ति देने के बाद अस्थर्था का चयन निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख पशुपालन सचिव और निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस

- हाई कोर्ट ने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक तथा कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी किया।

जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने ये आदेश अशोक कुमार धाकड़ की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर, 2023 में पशु (शेष पृष्ठ 4 पर)

भारत में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेयर अर्थ की डिपॉज़िट्स हैं, पर आज भी ज़मीन का माल ज़मीन में ही क्यों रह गया है

कागज़ी कार्यवाही इतनी गलाघोट है कि खनिज की डिस्कवरी और खान को प्रोडक्शन में आने में पंद्रह साल लग जाते हैं

- पर, 2023 में कुछ आशा जगी, क्योंकि 1957 के माइंस एण्ड मिनरल्स एक्ट में सरकार को परिवर्तन करना पड़ा और प्राइवेट सैक्टर को भी रेयर अर्थ के खनिजों को खोद कर निकालने की सुविधा मुहैया कराई है।

- यह परिवर्तन इसलिए हुआ, क्योंकि सरकार को यह अहसास हो गया कि केवल सरकारी कॉर्पोरेशन को ही माइनिंग का अधिकार प्राप्त रहेगा तो मिनरल का एक्सप्लॉयटेशन कभी पूरा नहीं हो पायेगा।

- चीन में जिस दिन मिनरल मिलता है, दूसरे दिन ही खुदाई शुरू हो जाती है। जब तक भारतीय खान मालिक पुरानी खान नीति के तहत परमिशन को ढूँढ़ रहा होता है, चीन का माल बाज़ार में आ चुका होता है।

परिवर्तन तक, यह कहानी उन टैक्टीक बदलावों को उजागर करती है, जो भौगोलिक संपत्ति को राष्ट्रीय शक्ति में बदलने के लिए आवश्यक है। भारत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों के सबसे समृद्ध भंडारों में से एक है, फिर भी दशकों की

नीति संबंधी निष्क्रियता, लालफीताशाही और सावधानी की गलत सोचने इस भौगोलिक खजाने को जमीन में ही बंद कर दिया है, जबकि चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भारत के प्राचीन उपमहाद्वीपीय ढाल के नीचे एक भौगोलिक धरोहर है,

जो देश को महत्वपूर्ण खनिज सुपरपावर के रूप में स्थापित कर सकती है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व, लिथियम, निकल, टाइटेनियम (वह कच्चा माल जो एवन टरबाइन, लड़ाकू विमानों, और स्मार्टफोन बैटरियों से लेकर सभी चीजों को शक्ति प्रदान करता है) इस भूमि पर

प्रचुर मात्रा में हैं, यह कभी गोंडवाना भूमि का हिस्सा थी, जो पैजिया सुपरमहादीप का दक्षिणी भाग था।

आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बयान करते हैं। भारत के पास लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ पृथ्वी के भंडार हैं, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। देश में लगभग 30 महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिनमें से बड़े भंडार कर्नाटका के मंड्या जिले के लिथियम क्षेत्रों से लेकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के मोनाजाइट-समृद्ध तटीय रेतों तक फैले हुए हैं।

फिर भी, यह भौगोलिक संपत्ति अधिकांश रूप से उपयोग नहीं की गई है, जो तकनीकी कमियों और पुराने ढांचों के कारण बंद पड़ी है। हालाँकि, 2023 के बाद के नीति परिवर्तनों ने एक नया युग शुरू किया है। “चन्नमल्लिकार्जुन बी. पटिल, जो

संस्थापक हैं, कहते हैं। भारत ने नक्शा बनाने और प्रारंभिक अन्वेषण के मामले में अद्भुत काम किया है,” देश का लगभग 95-98 प्रतिशत क्षेत्र इस सम्बंध में कवर किया गया है, इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन और कंसल्टेंसी लिमिटेड, और परमाणु खनिज निदेशालय जैसी संस्थाओं का धन्यवाद।”

यह आधारभूत कार्य भारत को खनिज विकास के अगले चरण में तेजी से प्रवेश करने की स्थिति में ला सकता है।

उन्होंने कहा, “यह एक बहुत बुनियादी संकेतक है, और यह पर्याप्त डेटा प्रदान नहीं करता। दुनिया यह जानना चाहती है कि भारत के पास इन महत्वपूर्ण खनिजों में से वास्तव में (शेष पृष्ठ 4 पर)

जयपुर डिस्कॉम उपभोक्ताओं से “ स्टार रेटिंग ” फीडबैक लेगी- भजनलाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीनों डिस्कॉम ने दिवाली से पहले 37 हजार विद्युत कनेक्शन दिए

जयपुर, 25 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार, प्रदेश में आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर डिस्कॉम्स ने निरंतर विद्युत सेवाओं में सुधार करते हुए इन्हें उपभोक्ता अनुकूल एवं जवाबदेह बनाने के नवाचार किए हैं।

प्रदेश के तीनों डिस्कॉम्स ने दीपावली से पूर्व विशेष अभियान चलाकर प्रदेशभर में 37 हजार 251 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए हैं। जयपुर डिस्कॉम ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए “स्टार रेटिंग” का फीडबैक सिस्टम संबंधी नवाचार भी प्रारंभ किया है।

तीनों डिस्कॉम्स ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत लॉन्च प्रकरणों के साथ-साथ नए प्रकरणों में दस्तावेज की जांच, साइट वेरीफिकेशन, डिमांड नोट जारी करने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सहित, अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कर कनेक्शन प्रदान किए गए।

जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत कनेक्शन जारी करने में आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी लेने

- “बिजली मित्र” एप्लीकेशन में उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त करने के अनुभव को “स्टार रेटिंग” देगा। हर माह के अंत में सब डिविजन लेवल पर समीक्षा होगी। इसके अनुसार अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता कार्यालय की रैंकिंग तय होगी।

एवं निचले स्तर तक मॉनीटरिंग को आसान बनाने के लिए स्वतंत्र फीडबैक सिस्टम का नवाचार किया है। इस मैकेनिज्म में नया घरेलू कनेक्शन जारी होने के बाद आवेदक को मोबाइल एप्लीकेशन “बिजली मित्र” डाउनलोड करने का एसएमएस प्राप्त होगा।

एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही “के” नम्बर डालने पर उपभोक्ता को फीडबैक पॉप अप दिखाई देगा। इस पॉप अप पर क्लिक करते ही उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त करने के अपने अनुभव 1 से 5 स्टार रेटिंग के जरिए प्रदान कर सकेगा। इनकी वृत्त तथा सब डिविजन स्तर पर प्रत्येक माह

उदयपुर, 25 अक्टूबर। शहर के समीप डबोक थाना क्षेत्र में एनिकट में नहाने के लिए गये चार बच्चों की गहराई में जाने से डूबने से मौत हो गई। मृतकों में तीन सगे भाई-बहन हैं। एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ और चारों की मौत हो गई।

थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि मनोहर (6) पुत्र राजू कालबेलिया, कोमल (8) पुत्री राजू कालबेलिया, पायल (10) पुत्री राजू कालबेलिया और सुमन (16) पुत्री केशू कालबेलिया निवासी लक्ष्मणपुरा काकरनाडा भमरासिया घाटी- चारों की डूबने से मौत हो गई।

इन बच्चों के परिवार की बकरियां चरने गई थी। परिजनों ने बच्चों से बकरियों को तलाश कर वापस घर लाने को कहा था। चारों बच्चे एक साथ गए थे और एनिकट में नहाने लगे। एक बच्चे का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए बाकी तीन बच्चों ने

नियुक्ति के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिचर के करीब छह हजार पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया। गत 29 सितंबर को याचिकाकर्ता को अजमेर जिले में नियुक्ति दी गई।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 13 अक्टूबर को उसकी नियुक्ति को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा गया कि उसके खिलाफ साल 2022 में साधारण मारपीट को लेकर मामला दर्ज हुआ था। वहीं, पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण को झूठा पाकर मामले में एफआर पेश कर दी। दूसरी ओर विभाग ने उसकी नियुक्ति को रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया।

ऐसे में उसकी नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीट ने याचिकाकर्ता को हटाने के आदेश पर अंतिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

उदयपुर के पास एनिकट में डूबने से चार बच्चों की मौत

- चारों बच्चे चरने गई बकरियों को वापस लाने गए थे और एनिकट में नहाने लगे। एक बच्चा पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया। उसको बचाने के प्रयास में बाकी तीन भी डूब गए।

प्रयास किए और एक को बचाने के प्रयास में एक-एक कर वे तीनों भी पानी में डूब गए। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने इस बारे में गांव में जाकर बताया।

मौके पर ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के साथ ही बच्चों की तलाश शुरू कर दी। मौके पर पुलिस भी

जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवंई की आगामी 23 नवंबर पर सेवानिवृत्ति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कानून और न्याय मंत्रालय ने न्यायमूर्ति गवंई को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम को अनुशंसा करने का अनुरोध किया है। स्थापित परंपरा और नियुक्ति की कार्यविधि के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया जाता है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गवंई के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं।

न्यायमूर्ति गवंई द्वारा की गई अनुशंसा पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत औपचारिक रूप से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा।

दस फरवरी 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1981 में

पहुँची और पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम को सूचित किया। सूचना पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय व्यक्तियों ने सभी शवों को बाहर निकाल कर डबोक पुलिस को दे दिया था। मौके पर पांच जोड़ी कपड़े होने पर एक बच्चे के और होने की आशंका पर ढूंढने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम ने सर्व ऑपरेशन जारी किया । परंतु कोई नहीं मिला। टीम में गोताखोर विजय नकवाल, विपुल चौधरी, दिनेश गमेती, सचिन कंडाया, प्रकाश राठौड़, जगदीश कुमावत एवं वाहन चालक कैलाश मेनारिया मौजूद रहे।

सूचना मिलने पर, मौके पर वल्लभनगर तहसीलदार सुरेन्द्र छीपा पहुंचे। तहसीलदार ने मृतक आश्रितों को सरकारी आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। बाद में बच्चों का पोस्टमार्टम करवाकर, शव परिजनों के सुपुर्द कर दिये।

भारत में विश्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कितना है और कहां कहां है।" चीन के साथ इसका अंतर केवल क्षमता के अंतर को नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि में भी एक गहरे अंतर को उजागर करता है।

दशकों पहले जब दुनिया ग्लफ तेल पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तब चीन ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के मूल्य को पहचाना था। तब वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लगभग 95 प्रतिशत बाजार तकनीक पर चीन का कब्जा है। जो लगभग सभी स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, रक्षा प्रणालियों, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कच्चे माल के रूप में काम करती है। 2023 में एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब खनिजों और खनिज संसाधनों (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 को संशोधित किया गया, ताकि 29 महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति मिल सके।

अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत एक दार्शनिक परिवर्तन को दर्शाती है, यह स्वीकार करते हुए कि केवल सरकारी एजेंसियां भारत की खनिज संपत्ति को नहीं खोल सकतीं। लगभग 20 कंपनियों ने इस नीति परिवर्तन का लाभ उठाया है, जिनमें से कुछ ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पटिल की अपनी कंपनी, वर्तमान में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित दो दुर्लभ पृथ्वी अन्वेषण परियोजनाओं में शामिल है, और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं।

फिर भी, यह प्रगति भारत में खनिज अन्वेषण की कठोर वास्तविकता को उजागर करती है।

पटिल के अनुसार “आमतौर पर, अन्वेषण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है,” पहले, एछाली सरकार की नीतियों के कारण, खनिज की खोज से उत्पादन तक लगभग 14 से 15 साल का समय लगता था”

‘मई 2025 में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद गौतम अडानी और उनके सात सहयोगियों पर अमेरिका में आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारत में महंगे सोलार पावर अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की व्यवस्था की, जबकि मोदी सरकार ने लगभग एक साल तक अमेरिकी एक्सईसी सम्मन को प्रधानमंत्री के इस सबसे पसंदीदा व्यापार समूह तक पहुंचने ही नहीं दिया।

कुरनूल बस हादसे का बड़ा कारण था, 2 3 4 स्मार्ट फोन्स का 4 6 लाख रु. का पार्सल

फॉरैनसिक विशेषज्ञों ने बताया जब बस में आग लगी तो स्मार्ट फोन्स की बैटरियों में धमाके होने से आग भीषण हो गई और तेजी से बस जलकर खाक हो गई

हैदराबाद, 25 अक्टूबर। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस में आग लगने की घटना में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि है जिस बस में आग लगी, उसमें 234 स्मार्टफोन्स का एक पार्सल रखा था। जब बस में आग लगी तो इन स्मार्टफोन्स की बैटरियों में धमाका हुआ, जिससे आग और भीषण हो गई और लोगों को बचने का समय नहीं मिल पाया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, हैदराबाद के एक व्यापारी ने 234 स्मार्टफोन्स का एक पार्सल बस में रखवाया था। यह पार्सल बंगलूरु में ई-कॉमर्स कंपनी के

- प्रत्यक्ष दर्शियों ने भी कहा कि जब बस में आग लगी तो उन्होंने भी धमाकों की आवाज सुनी थी।

पास जाना था, जहां से ये स्मार्टफोन्स ग्राहकों को डिलीवर होने थे। इन स्मार्टफोन्स की कीमत करीब 46 लाख रुपये थी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब बस में आग लगी तो उन्होंने धमाके की आवाज सुनी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि यह धमाका स्मार्टफोन्स की बैटरियों के फटने से हुआ होगा। इससे आग ने तेजी से बस को अपनी चपेट में ले लिया और लोगों को बचने का मौका नहीं

मिला। शुक्रवार को कुरनूल में हुए बस अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश अग्नि सेवा विभाग के महानिदेशक प्रो. वेंकटरमन ने ये भी बताया कि स्मार्टफोन्स की बैटरियों के साथ ही बस के एयर कंडीशनर की बैटरी में भी धमाका हुआ, जिससे आग और भीषण हुई। उन्होंने बताया कि आग इस कदर तेज थी कि बस के फ्लोर की एल्युमीनियम की शीट भी पिघल गई। उन्होंने बताया कि बस द्वारा बाइक को

टक्कर मारने के बाद, जब बस ने बाइक को घसीटा तो उससे पेट्रोल बिखर गया और जैसे ही चिंगारी निकली बस ने तेजी से आग पकड़ ली। शुरुआत में बस के अगले हिस्से में आग लगी, जिसने तेजी से पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। वेंकटरमन ने ये भी बताया कि बस की बनावट में भी खामियां थीं। उन्होंने कहा कि बस को हल्का रखने और तेज गति देने के लिए बस के फ्लोर की शीट एल्युमीनियम की बनाई गई थी, जबकि यह लोहे की होनी चाहिए थी। एल्युमीनियम की चादर को आग से हुए नुकसान के चलते बचाव अभियान में परेशानी हुई और हादसे की भयावहता बढ़ी।

भगोड़े लखविंदर कुमार को सीबीआई भारत लाई

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। भगोड़े अपराधी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गे लखविंदर कुमार को सीबीआई अमेरिका से भारत लेकर आई है। अधिकारियों के मुताबिक, लखविंदर कुमार के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था।

दस से पन्द्रह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सबसे पहले शुरू होगा। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह के मध्य में एस.आई.आर. के पहले चरण की घोषणा कर सकता है, जिसमें “10 से 15” राज्य शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग उन राज्यों में मतदाता सूची संशोधन का काम नहीं करेगा, जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर चुनाव मशीनरी इसमें व्यस्त है और एस.आई.आर. पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पा रही है। ऐसे राज्यों में एस.आई.आर. बाद के चरणों में आयोजित किया जाएगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2008/27147** जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन रोड आयद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्स्टीटयल परिया, फेस प्रथम, जालोर।फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2008/27147** जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन रोड आयद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्स्टीटयल परिया, फेस प्रथम, जालोर।फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

$$\begin{array}{ccccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \oplus & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \oplus & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \oplus & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{array}$$



गोल्ड ₹14000/Gram
कोठी ₹4700/Sq Ft •
फ्लैट ₹4000/Sq Ft

सोने से सस्ती कोठी

सोने से ज्यादा रफ्तार
से बढ़ते प्राइस

पजेशन पर ₹10 लाख प्राइस बढ़ेगी !

64 दिनों में हैंडओवर शुरू



FIXED PRICE & RENTAL

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE	PROPOSED RENTAL (AFTER POSSESSION)
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 LACS	22,000
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 LACS	25,000
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 LACS	28,000
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 CRORE	30,000
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.10 CRORE	40,000
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.50 CRORE	50,000



अजमेर रोड़, जयपुर

बड़ी-बड़ी कोठी, बड़े-बड़े फ्लैट

SCAN QR FOR
• LOCATION
• ROUTE MAP
• SITE 360 TOUR
• E-BROCHURE
• WALKTHROUGH



info@kedia.com

www.kedia.com

www.rera.rajasthan.gov.in
RERA No. RAJ/P/2023/2387

T&C Apply.

घर के लिए:

☎ 1800 120 2323

हमारे प्रॉडक्ट्स महँगे नहीं
आजकल लोगों को
सेहत सस्ती लगती है



KEDIA™ Pavitra

आटा । सूजी । दलिया । बेसन । गेहूँ
खड़े मसाले । कुकिंग ऑयल । दाल । चावल
ड्राई फ्रूट्स । चाय इत्यादि

ORDER
ON WEBSITE



ORDER
ON APP



ORDER
ON WHATSAPP



T&C Apply.

घर की ग़ोसरी के लिए:

☎ 1800 120 2727